



सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिनों बाद सुरक्षित निकाला गया

अनिवार्य प्रश्न। संवाद उत्तरकाशी। उत्तराखंड के 17 दिनों के लंबे और कठिन अभियान के बाद, बचावकर्मियों ने लोंग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी चुनौती पार की जा नहीं खोया। इन मजदूरों की कहानी हमें यह



उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिनों बाद सुरक्षित निकाल लिया गया है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने पूरे देश को खुशी और राहत दी है। घटना 21 नवंबर 2023 को हुई थी, जब सिलक्यारा सुरंग में एक मलबे की घटना में 41 मजदूर फंसे गए थे। सुरंग उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा गांव में स्थित है और यह उत्तरकाशी शहर को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से जोड़ती है।

मलबे की घटना के बाद, एनडीआरएफ और अन्य बचावकर्मियों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया। बचावकर्मियों ने सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत की। अंततः 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया। मजदूरों को मलबे से निकालने के लिए बचावकर्मियों ने कई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें ड्रिलिंग, खुदाई और सुरंग की दीवारों को तोड़ना शामिल था। सुरंग से निकाले गए मजदूरों में से 38 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। सभी मजदूरों की हालत स्थिर है और उन्हें अस्पताल में भेटी कराया गया है।

इस घटना के बाद, उत्तराखंड सरकार ने सुरंग की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। इस घटना ने देश भर में लोगों को एकजुट किया है। देश के कोने-कोने से लोग 41 मजदूरों के सुरक्षित बचाव के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इस घटना ने यह भी दिखाया कि जब

सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम एक-दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं, तो कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। अब होगी सुरंग हादसे की जांच सुरंग हादसे के बाद, उत्तराखंड सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया है। समिति को हादसे की वजहों की जांच करनी है और यह सुझाव देना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। जांच समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया है कि सुरंग हादसे का मुख्य कारण सुरंग निर्माण के दौरान मानकों का पालन नहीं करना था। समिति ने यह भी कहा है कि सुरंग में सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं थे। जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद, सरकार हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

देव दीवाली पर स्वर्ण किरणों से सजी काशी, फीका हुआ स्वर्ण रंग-बिरंगी रौशनी से जगमग दिखी काशी

अनिवार्य प्रश्न। संवाद वाराणसी। सोमवार 27 नवंबर, 2023 को देव दीवाली के मौके पर काशी दिव्यों की किरणों से जगमग दिखी। शाम के समय से पूरी रात पूरी काशी रंग-बिरंगी रौशनी से जगमग दिखी। प्राप्त सूचना के मुताबिक काशी के कुल 85 घाटों पर 12 लाख दीये जलाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस दौरान वहाँ उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तस्वीरें शेयर किया और लिखा, देव दीवाली के पावन अवसर पर आशा, आस्था, आत्मीयता और अंत्योदय के असंख्य दीव्यों के दिव्य प्रकाश से जगमग अविनाशी काशी।



पहली बार 70 देशों के राजदूत व प्रतिनिधि भी देव दीवाली के घाटों पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि जले अनुमानित 12 लाख दीव्यों में से 1 लाख दीये गाय के गोबर के थे। बाबा विश्वनाथ मंदिर को सजाने के लिए 11 टन फूल

मंगाए गए थे। केंद्रीय आवासीय, शहरी मामलों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी समारोह में मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विदेशी मेहमानों का स्वागत भी किया। कुल 150 विदेशी मेहमान काशी में उपस्थित थे। इससे पहले अयोध्या भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में शामिल हुआ था। राम जी की अयोध्या में 22.23 लाख दीये जलाए गए थे। उल्लेखनीय है कि देव दीवाली कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है। इस दिन सभी देवतागण स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस राक्षस का वध करने के बाद सभी देवतागण भगवान शिव से मिलने काशी नगरी पहुंचे थे। जहां देवताओं ने गंगा स्नान किया और फिर दीपदान कर खुशियां मनाईं। इसलिए काशी में इस पर्व को

बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। काशी नगरी भगवान शिव की नगरी है। इस नगरी में भगवान शिव के कई मंदिर स्थित हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी नगरी में देव दीवाली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी के घाटों पर लाखों दीपक जलाए जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत ही मनमोहक होता है। देव दीवाली के दिन काशी नगरी में कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। देव दीवाली के दिन काशी नगरी में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में संगीत, नृत्य, कविता पाठ आदि शामिल होते हैं। देव दीवाली का पर्व काशी नगरी के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और खुशियां मनाते हैं।

दुनिया में तेजी से बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग

इलेक्ट्रॉनिक वाहन पारंपरिक वाहनों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल

आजकल दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। यह एक सकारात्मक विकास है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन पारंपरिक वाहनों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल हैं।

चीन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग में दुनिया का अग्रणी देश है। 2022 में, चीन में 2.6 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए, जो कि दुनिया के कुल बिक्री का लगभग 50% है। चीन सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई

कदम उठा रही है, जिसमें सब्सिडी, कर छूट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास शामिल हैं। अन्य देशों में भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग में वृद्धि हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, 2022 में 692,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 83% अधिक है। यूरोपीय संघ में, 2022 में 2.3 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 60% अधिक है।

हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग में कुछ चुनौतियां भी हैं। इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक वाहनों की तुलना में अभी अधिक महंगे पड़े रहे हैं। इन वाहनों को चार्ज करने के लिए पर्याप्त चार्जिंग

स्टेशनों की कमी है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकारों और उद्योगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग

भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग में वृद्धि हो रही है। 2022 में, भारत में 300,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 100% अधिक है। भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार इनकी खरीद पर सब्सिडी देना शुरू कर दी

है। साथ ही ई-वाहनों पर कर छूट भी दी जाने लगी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30 तक पहुंचाना है।

दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। यह एक सकारात्मक विकास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन पारंपरिक वाहनों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल हैं। यह बात और भी अच्छी है कि भारत में

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की मणिपुरी रीति-रिवाजों से हुई शादी

इंफाल। फिल्मी अभिनेता रणदीप हुड्डा ने विगत 30 नवम्बर, 2023 की रात को मणिपुरी रीति-रिवाजों से अपनी लंबे समय से प्रेमिका लिन लैशराम से शादी कर ली। शादी मणिपुरी की राजधानी इंफाल में एक निजी समारोह में हुई। रणदीप और लिन पिछले चार सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों की मुलाकात एक थिएटर प्रोडक्शन के दौरान हुई थी। रणदीप ने लिन को पहली बार देखते ही उन्हें पसंद कर लिया था। उन्होंने लिन को अपने परिवार से भी मिलवाया और दोनों के परिवारों ने भी एक-दूसरे को स्वीकार कर लिया। शादी समारोह में केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए। रणदीप ने सफेद धोती-कुर्ता पहना था, जबकि लिन ने पारंपरिक मणिपुरी पोलाई पहनी थी। दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे।



परम्परा और संस्कृति का दिखा प्रेम शादी के बाद रणदीप और लिन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर अपने फैस को इस खुशखबरी से अलग करवाया। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा, जस्ट मैरिड। रणदीप और लिन की शादी को लेकर बॉलीवुड के उनके दोस्तों और फैस ने भी उन्हें बधाई दी। कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर उन्हें शादी की शुभकामनाएं दीं। रणदीप हुड्डा बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में दी हैं, जिनमें 'ओमकारा', 'रंग दे बसंती', 'बैड बाजा बारात', 'पद्मावत', 'सरदार उधम' और 'आरआरआर' शामिल हैं। लिन लैशराम एक मणिपुरी अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने कई मणिपुरी फिल्में और टीवी शो में काम किया है। रणदीप और लिन की शादी एक खूबसूरत और यादगार समारोह था। प्रसंशक दोनों को एक-दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिताने की कामना कर रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वाहन पारंपरिक वाहनों की तुलना में वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में काफी कमी करते हैं। इन वाहनों की तकनीक में सुधार हुआ है,

जिससे उनकी सीमा और प्रदर्शन में वृद्धि हुई है। कई सरकारें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और प्रोत्साहनों की पेशकश कर रही हैं। सरकारों का ममनना रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग में वृद्धि से पर्यावरण को काफी लाभ हो सकता है। इन वाहनों से वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी।

हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग में कुछ चुनौतियां भी हैं। इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक वाहनों की तुलना में अभी अधिक महंगे पड़े रहे हैं। इन वाहनों को चार्ज करने के लिए पर्याप्त चार्जिंग

स्टेशनों की कमी है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकारों और उद्योगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग

भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग में वृद्धि हो रही है। 2022 में, भारत में 300,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 100% अधिक है। भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार इनकी खरीद पर सब्सिडी देना शुरू कर दी

है। साथ ही ई-वाहनों पर कर छूट भी दी जाने लगी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30 तक पहुंचाना है।

डॉ. राम मूर्ति प्रसाद मिश्रा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

पता : इटैई, पोस्ट : बलुआ, ब्लाक : बड़ागांव, वाराणसी-221201
Center Code : UP 215

D.Ed विशेष शिक्षा समकक्ष Del.Ed./BTC

प्रवेश प्रारम्भ सुनिश्चित नौकरी

➔ भारतवर्ष के किसी भी राज्य में सरकारी शिक्षक एवं विशेष शिक्षक बनने का मिलेगा अवसर।
➔ समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बनने का अवसर।

निदेशक डॉ. ज्योति भूषण मिश्रा

प्रभारी : अतुल उपाध्याय : 7068383838
8765407836, 6393032960

मान्यता : भारतीय पुनर्वात परिषद, नई दिल्ली (भारत सरकार)
प्रारंभिक विद्यार्थियों में निम्नलिखित हेतु उत्तर प्रदेश एवं भारत के सम्प्रत राज्यों में मान्य।

Write on mail : rmpmishragitafoundation@gmail.com

बिहार की नीतीश सरकार ने रचा इतिहास

पहली बार पेश किये गये जातीय गणना से जुड़े आर्थिक आंकड़े

पटना । 18 साल में ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी और बाकी समय राष्ट्रीय जनता दल-कांग्रेस के साथ मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की सरकार ने मंगलवार को इतिहास रच दिया। देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना कराने के बाद जाति आधारित आर्थिक सर्वेक्षण भी पहली बार ही पेश किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में यह रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के 2 करोड़ 76 लाख 68 हजार 930 परिवारों में से 34.13 प्रतिशत, यानी 94 लाख 42 हजार 786 परिवार गरीब हैं। इनमें मुख्य रूप से पांच कोटियां हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों के गरीब परिवार सबसे ज्यादा 42.93 प्रतिशत हैं, जबकि सामान्य वर्ग के

गरीब परिवार सबसे कम होकर भी 25.09 फीसदी हैं।

02 अक्टूबर को गांधी जयंती के

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट	
34% परिवारों की मासिक आय 6 हजार से कम	
आय	परिवार (लाख)
₹ 4,000	94.42*
₹ 4,000-10,000	81.91
₹ 10,000-20,000	49.97
₹ 20,000-50,000	27.20
₹ 50,000+	10.79
अज्ञात/नहीं	12.37

(* परिवार प्रतिशत से नहीं कोर है)

दिन नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी। उसी रिपोर्ट से जुड़ा यह आर्थिक

सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है। जैसे उस रिपोर्ट में लगभग हर एक आदमी की गणना का दावा देखते हुए उसे जनगणना माना गया, उसी तरह इसे वास्तविक स्थिति ही माना जाना चाहिए। इस हिसाब से इस रिपोर्ट को देखें तो बिहार में सबसे ज्यादा 98 लाख 84 हजार 904 परिवार अत्यंत पिछड़ी जातियों के हैं, जिनमें 33.58 प्रतिशत यानी 33 लाख 19 हजार 509 परिवार गरीब हैं। परिवार की संख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर पिछड़ा वर्ग हैं। पिछड़ा वर्ग के राज्य में 74 लाख 73 हजार 529 परिवार हैं, जिनमें 33.16 प्रतिशत यानी 24 लाख 77 हजार 970 परिवार गरीब हैं। तीसरे नंबर पर अनुसूचित जातियों के परिवार की

संख्या है। राज्य में अनुसूचित जाति के 54 लाख 72 हजार 024 परिवार हैं, जिनमें 42.93 प्रतिशत यानी 23 लाख 49 हजार 111 परिवार गरीब हैं (सरकार की ओर से कोटिवा आधार पर बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री ने आरक्षण बढ़ाने के साथ-साथ सभी गरीबों को आर्थिक मदद का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। बुधवार को कार्यवाही शुरू होने के साथ ही यह बात आगे बढ़ेगी और सरकार इसी सत्र के बाकी तीन दिनों के अंदर सारे प्रस्तावों को अधिसूचना के रूप में जारी कर सकती है।

282 हैं, जिनमें 25.09 प्रतिशत परिवार गरीब हैं। यानी, 10 लाख 85 हजार 913 परिवार सामान्य वर्ग में होकर भी गरीब हैं। पांच प्रमुख कोटियों के अलावा, इस रिपोर्ट में अन्य प्रतिवेदित जातियों का एक कॉलम रखा गया है, जिनके परिवार की कुल संख्या 39 हजार 935 बताई गई है। इनमें 23.72 प्रतिशत, यानी 9474 परिवार गरीब हैं।

सभी गरीबों को आर्थिक मदद का रखा प्रस्ताव

पटना। देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन असली चुनावी मोड़ बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान में राज्य की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार है। जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री ने आरक्षण बढ़ाने के साथ-साथ सभी गरीबों को आर्थिक मदद का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। बुधवार को कार्यवाही शुरू होने के साथ ही यह बात आगे बढ़ेगी और सरकार इसी सत्र के बाकी तीन दिनों के अंदर सारे प्रस्तावों को अधिसूचना के रूप में जारी कर सकती है।

सोनिया-राहुल गांधी को बड़ा झटका: ईडी ने जब्त की यंग इंडिया, एजेएल की 752 करोड़ की संपत्ति

दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने गत दिनों को बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस से जुड़े एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड

जांच के दौरान यह पाया गया कि AJL और Young Indian को देश के कई शहरों में फैली अचल संपत्तियां अवैध रूप से प्राप्त

शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में फैली 661.69 करोड़ की संपत्तियां अपराध से प्राप्त की गई है। प्रवर्तन निदेशालयमालूम हो कि 1937 में ए एसोसिएटेड नाम से कंपनी बनाई गई थी, इसके मूल निवेशकों में जवाहरलाल नेहरू समेत 5,000 स्वतंत्रता सेनानी थे। यह कंपनी नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कोली आवाज अखबारों का प्रकाशन करती थी। धीरे-धीरे कंपनी घाटे में चली गई और कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपये का लोन देकर कंपनी को घाटे की उबारने की कोशिश की। हालांकि, वह सफल नहीं हो पाई इसी बीच 2010 में यंग इंडिया के नाम से एक अन्य कंपनी बनाई गई, जिसमें 76 प्रतिशत शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास और 12-12 प्रतिशत शेयर मोतीलाल बोरा और आस्कर फर्नांडिस के पास था। कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया।



और यंग इंडिया के 752 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे कई शहरों में फैले संपत्ती को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है प्रवर्तन निदेशालय ने अपने एक बयान में कहा कि मामले की

की गई हैं निशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने करोड़ों रुपये की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का आदेश जारी किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में 751.9 करोड़ रुपये की जांच की गई, जिसमें पता चला कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के पास भारत के कई

साहित्य में काशी का लहराया परचम

स्मारिका विमोचन, लखनऊ में सर्वसम्मति से मनोनयन

लखनऊ। विश्व विद्यालय द्वितीय परिसर के ज्यूरियस हॉल, प्रशासनिक भवन में विभव जन चेतना ट्रेड भारत का पाँचवाँ वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह सुशीला धरमना 'मुस्कान' की अध्यक्षता, वशीधर सिंह के मुख्य आथिल्य एवं कंचन सिंह परिहार के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। जिसमें विभिन्न प्रांतों से व देशों से आए 28 कवियों, कवयित्रियों को शाल, शील्ड, अकिर सम्मानित किया गया। समारोह में आ. राहुल शुक्ल साहित्य, राजेश मिश्र श्रयास, डॉ. शरद श्रीवास्तव 'शरद', आ. गीताजलि वार्णेय 'सुवांजलि' ईंजी. हेमना कुमार 'सिंहर्द', आ. शैलबाला कुमारी के प्रतिनिधि जे. आर. सैनी को मधु-स्मृति सम्मान-2023 से सम्मानित किया गया।



वहीं आ. नीतेन्द्र कुमार सिंह परमार 'भारत', पं. सुमित शर्मा 'पीयूष' आ. ओम प्रकाश फुलारा 'प्रफुल्ल' को साहित्य प्रेरणा सम्मान-2023 से गौरवान्वित किया गया। कवि शरद कुमार श्रीवास्तव 'शरद' जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुशीला धरमना 'मुस्कान' राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक मण्डल, संतोष कुमार 'प्रीत' को

राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतेन्द्र सिंह परमार 'भारत' को राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालक नियुक्त करते हुए सभी को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए गए। दिनेश अवस्थी जी को शरद रत्न पुरस्कार -2023 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था की स्मारिका का लोकार्पण किया गया तथा केक काटकर संस्था का वार्षिकोत्सव सहर्ष मनाया गया।

भारत ने सफलतापूर्वक किया प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण

बालासोर। भारत ने सफलतापूर्वक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि यह परीक्षण ऑडिटा तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। बता दें कि प्रलय मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। अधिकारियों ने बताया यह परीक्षण अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। ट्रैकिंग उपकरणों से मिसाइल की ट्रेजेक्टरी का विश्लेषण किया गया। बता दें कि प्रलय मिसाइल की रेंज 350-500 किलोमीटर है और यह 500-1000 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल एलएसी और एलओसी पर तैनाती के लिए विकसित की गई है। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि चीन डोंग फेंग 12 और रूस की इस्केंडर मिसाइलों की तुलना भारत की प्रलय मिसाइल से हो सकती है। यूक्रेन युद्ध में रूस ने इस्केंडर मिसाइल का खूब इस्तेमाल किया है। बता दें कि पाकिस्तान के पास भी इस रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। गौरतलब है कि एक महीने पहले ही भारतीय वायुसेना ने लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में यह परीक्षण किया गया, जिसमें फाइटर जेट सुखोई-30एमकेआई से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के सबसे घातक हथियारों में से एक है।

आपराधिक कानूनों का नाम हिंदी में करने के फैसले पर मुहर

नई दिल्ली। सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत के दौर में बने कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य कानून में बदलाव की पहल की है। इस महीने की शुरुआत में, संसदीय पैल ने कई संशोधनों की पेशकश की थी, लेकिन कानूनों के हिंदी नामों पर कायम रहे। कानूनों के नाम हिंदी में होने के फैसले पर करीब 10 विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया। राजनीतिक दलों द्वारा लगातार इस कदम को अस्वीकार करने पर संसद की एक समिति ने मंगलवार को साफ कर दिया कि तीन प्रस्तावित आपराधिक कानूनों का नाम हिंदी में होना अवैधानिक नहीं है। भाजपा सांसद बृजलाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने संविधान के अनुच्छेद 348 को संज्ञान में लिया। दरअसल, अनुच्छेद 348 के अनुसार शीर्ष अदालत और हाईकोर्ट के साथ-साथ अधिनियमों, विधेयकों और अन्य कानूनी दस्तावेजों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए।

नई दिल्ली। सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत के दौर में बने कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य कानून में बदलाव की पहल की है। बीते अगस्त में संसद के मानसून सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय

था, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि विधेयकों को हिंदी नाम नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जब अंग्रेजी को इस्तेमाल किया जाता है तो इनके नाम अंग्रेजी में दिए जाने चाहिए। अगर हिंदी का इस्तेमाल किया जाता तो हिंदी नाम दे सकते थे। हालांकि, जब कानूनों का मसौदा तैयार किया जाता है, तो यह अंग्रेजी में तैयार किया जाता है। वहीं, तमिलनाडु की सतारुद्र द्रविड़ मुनेत्र कडगम (डीएमके) ने भी प्रस्तावित आपराधिक कानूनों के लिए हिंदी नामों के उपयोग के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके अलावा, मद्रास बार एसोसिएशन ने तीनों विधेयकों का नाम हिंदी में रखने के केंद्र के कदम को संविधान के खिलाफ बताया है। एसोसिएशन ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया है।

दो पीसीएस अफसरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

लखनऊ। लखनऊ- वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग-56 के लिए भूमि अधिग्रहण में नियम विरुद्ध मुआवजा देने वाले दो पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अमेटी में एसडीएम के पद पर तैनात रहे दोनों अफसरों आरडी राम और अशोक कुमार कनौजिया ने किसानों को तीन गुना से अधिक मुआवजा बांट दिया था। इससे राज्य सरकार को 382 करोड़ रुपये की हानि हुई। प्रकरण में 11 अक्टूबर को अमेटी के मुसाफिरखाना थाने में दोनों अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ईडी ने इसे आधार बनाकर दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 2014 में एनएच-56 को फोरलेन करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुरोध पर राजस्व विभाग ने सड़क चौड़ीकरण के अलावा जगदीशपुर व मुसाफिरखाना में कच्चे से बाहर बाईपास बनाने के लिए सर्वे किया।

प्रस्तावित आपराधिक कानूनों के लिए हिंदी नामों के उपयोग के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके अलावा, मद्रास बार एसोसिएशन ने तीनों विधेयकों का नाम हिंदी में रखने के केंद्र के कदम को संविधान के खिलाफ बताया है। एसोसिएशन ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया है।

हर हाल में पराली जलना बंद हो-सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली वायु प्रदूषण के मुद्दे के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराने के लिए

सुनवाई कर रही थी। याचिकाएं राजस्थान राज्य से संबंधित थीं, जिसमें याचिकाकर्ता ने बताया कि पटाखा प्रतिबंध पर आधिपत्य का आदेश पूरे देश में लागू होना चाहिए, लेकिन यह दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित है।



केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी और पड़ोसी राज्यों में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। अदालत भारत में पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर

पराली जलाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि हम जो देख रहे हैं कि ये एक दोषारोपण का खेल है। हर कोई इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि इसका समाधान नहीं चाहता।

डीएम ने तहसील सभागार में की जनसुनवाई

अनिवार्य प्रश्न। संवाद वाराणसी। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम तथा डीसीपी गोमती प्रबल प्रताप सिंह द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस पर राजातालाब तहसील सभागार में जनसुनवाई की गयी। इस दौरान मिल्कीचक गंगापुर के छेदीलाल द्वारा विद्युत बिल में सुधार कराने के लिए चार समाधान दिवसों में आवेदन देने के बाद भी कोई कार्यवाही न किये जाने की शिकायत पर गहरी नाराजगी जताई और बताया कि 20 मई 2023 को 505 का बिल जमा किया गया और बकाया बिल रहा, इसके पश्चात 24 जुलाई 2023 को 500 का बिल जमा किया तो बकाया राशि 63910 की धनराशि अंकित कर दिया गया।

जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अभियंता के खिलाफ शासन को पत्र भेजने की निर्देश दिया। कुंडरिया गांव थाना परीक्षण किया गया, जिसमें फाइटर जेट पत्र दिया गया कि गांव के ही शिवबली पुत्र स्व. रामराज सिंह, सुभाष पुत्र स्व. धर्मराज व अन्य द्वारा सरकारी जमीन, बंजर पर पेड़ काट रहे हैं और मिट्टी डालकर कब्जा कर रहे हैं। आराजी नं. 989/1 रकबा 1.58डि. 1319 व 1334 के खाते में बंजर दर्ज है। वहीं आराजी नं. वर्तमान की खतीनी नं. 989/2 बंजर की भूमि में दर्ज 989/1, 989/2, 989/4 तथा 989/5 भिन्न- भिन्न भूमिधरी में दर्ज कराया गया है।

कानाना सरकारी जमीन को प्राइवेट की बिक्री के नाम चढ़ाने के लिए यह कार्रवाई निरर्थक करेगी। ग्राम भतसर, जन्सा के उमराल पाल 2 के भाई तथा पुत्रगण ने तय करने और निस्तारण करने के निर्देश एसडीएम राजातालाब को पत्र दिया। ग्राम करौती लोहता के अंकित सिंह द्वारा शिकायती पत्र दिया गया कि बंजर भूमि पर सैकड़ों वर्ष पुराना सार्वजनिक रास्ता कायम है। जिसे विपक्षीगण अभय नारायण सिंह पुत्र मुहम्मद सिंह व अन्य द्वारा गेट लगा कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। जिलाधिकारी ने एसडीएम को निर्देशित किया कि धारा 33/39 में बंजर जमीन को किस नियम के तहत आवंटित कराया गया। जांच करा कर आवश्यक कार्रवाई करें

और वृष्टि सुधार की कार्रवाई करें। भूमि की वास्तविक स्थिति ज्ञात होने पर ही अगली कार्रवाई निरर्थक करेगी। ग्राम भतसर, जन्सा के उमराल पाल 2 के भाई तथा पुत्रगण ने शिकायत की कि विपक्षीगण झरिहक पुत्र जगरदेव तथा झरिहक के पुत्रगण काशतकारी नहीं करने दे रहे हैं। जिसपर एसपी राजातालाब ने राजस्व टीम के साथ मौके पर जाकर शिकायत का निस्तारण कराने हेतु डीसीपी गोमती प्रबल प्रताप सिंह द्वारा निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने जौर देते हुए निर्देशित किया है कि किसी भी वाद के निस्तारण में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें और यदि किसी मामले में विधिक/नियम की जानकारी अपेक्षित हो तो एसडीएम अथवा वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में लायें तत्पश्चात् निस्तारण करें।

यूपी एटीएस ने आतंकीयों के मंसूबे पर फेरा पानी, दो गिरफ्तार

लखनऊ। यूपी एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े दो आतंकीयों को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। ये लोग यूपी में बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने अब्दुल्ला अर्सलान और माज बिन तारिक को गिरफ्तार किया है। एटीएस को उनके पास से आईएसआईएस से जुड़ा साहित्य और प्रोग्रामिंग की सामग्री से भरी पेन ड्राइव बरामद हुई है। एटीएस ने दोनों आतंकीयों को कोर्ट में पेश किया जल्द ही उन्हें कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा।

यूपी के पांच अस्पतालों में ई-आफिस प्रणाली होगी लागू-डिप्टी सीएम

लखनऊ। यूपी के पांच अस्पतालों में ई-आफिस प्रणाली लागू होगी। इसका मकसद कार्यालय के सभी पत्र, पत्रावली, फाइल का डिजिटलाइजेशन करना है। फाइल व पत्रावलियों को तलाशना आसान होगा। कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। फाइलों के गायब होने की आशंका कम होगी। कम समय में फाइलें खोजी जा सकेंगी।

मेंडिकल संस्थानों में ई-आफिस प्रणाली लागू की जाएगी। इसके लिए 7134. 90



लाख रुपये के बजट की व्यवस्था है। प्रथम चरण में संजय गांधी पीजीआई, डॉ. राम मनोहर लोहिया आधुनिक संस्थान, अस्पतालों से की गई है। प्रयोग सफल होने पर दूसरे मेंडिकल संस्थानों में व्यवस्था लागू की जायेगी।

केजीएमयू, कल्याण सिंह अतिविशिष्ट संस्थान तथा कानपुर स्थित राजकीय मेंडिकल कॉलेज में यह व्यवस्था लागू की जायेगी। पहली किस्त के रूप में 188.44 लाख की धनराशि जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यवाही संस्था यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन को जल्द से जल्द कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाटक ने कहा कि ई-आफिस एक डिजिटल वर्क प्लेस सॉल्यूशन है। इसे लागू करने की दिशा में कवायद तेज कर दी गई है।

नेताजी के बाद सपा में जनता की आवाज उठाने वालों को जगह नहीं

लखनऊ। सपा के महासचिव व पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनके साथ ही उनकी बेटी डॉ. पूर्वी वर्मा भी कांग्रेसी हो गईं।

कांग्रेस पार्टी समाज के हर तबके के हितों की रक्षा के लिए काम करती है।

के बाद डॉ. पूर्वी वर्मा ने एक्स पर फोटो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि बड़ों को



इसके पहले, शनिवार को पूर्व सांसद रवि वर्मा और उनकी बेटी डॉ. पूर्वी वर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। इस मुलाकात

आशीर्वाद लेकर अब आगे बढ़ने का समय है। इस फोटो के शेयर होने के बाद उनके समर्थकों और कांग्रेसियों ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया था।

अनिवार्य प्रश्न
हर कलम विकती नहीं!
www.anivaryaprashna.in

सरकारी विभागों के लिए सूचना

सभी पीआरओ / सूचना-अधिकारियों के लिए विवरण

कहाँ भेजें विज्ञापित या विज्ञापन

अपनी विज्ञापित या विज्ञापन या अपने समाचार व लेख निम्नलिखित पते पर भेजें!

कैसे करें आवेदन

हर प्रकार का विज्ञापित या विज्ञापन, समाचार, लेख अन्य जानकारी इत्यादि हमें नीचे के लिंक/पते पर सझा करे अथवा हमारे जगदीदी / जनप्रीय कार्यालय पर संपर्क करें!

News Line : 9161099088
anivaryaprashna@gmail.com

PRESS
अपार पत्रिक, तो सिर्फे तय किये!

मोम के आदमी का पत्थरी कंक्रीट से प्रेम, क्या होगा भविष्य?



“ क्या आप आग उगलती पत्थर की दुनिया देखना चाहेंगे? जैसे कई अनिवार्य प्रश्न पूछते हुए कंक्रीट के मानवीय लगाव के दुष्परिणाम को रेखांकित कर रहे हैं वरिष्ठ लेखक छतिश द्विवेदी 'कुंठित' ”

अनेक शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि मनुष्य धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। यहाँ तक की गीता भी मानव योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि बताती है, लेकिन मनुष्यों ने संसार को अपने अनुकूल बनाने में संसार का जितना नुकसान किया है इसकी बारी-बारी गिनती संभव नहीं है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु को अपने अनुकूल करते हुए अपनी कठिनाइयों को क्रमशः दूर करना चाहता है और अब तक करता रहा है। अंधेरे से बचने के लिए उसने रोशनी का निर्माण किया अर्थात् बिजली बनाई और बिजली से हजारों लोगों को लाभ तो हुआ लेकिन लाखों जिंदगियों को नुकसान भी पहुँचा है। इस तरह मनुष्य ने अपने घर मकान, रास्तों में जिस तरह से कंक्रीट का उपयोग किया है वह भी बेहिसाब किया है। कंक्रीट के उपयोग के लाभ से मुकरना तो संभव नहीं है ना ही ऐसा करना सही है लेकिन उसके नुकसान के सापेक्ष मौन रहना भी सामाजिक अपराध ही है। विगत दो चार दशकों में मानव समाज ने अपने घर मकान, कंपनी, जीवन के अन्य सरोकार के संसाधन व सड़क निर्माण में जिस तरह से कंक्रीट का उपयोग किया है उस उपयोग की गति बहुत भयावह है। अनेक चीजों के कई सम्मिलान के बाद तब कंक्रीट तैयार होता है लेकिन उसके सिर्फ एक अवयव सीमेंट की बात करें तो विगत एक दशक में सीमेंट के उपयोग में काफी वृद्धि हुई है। 2013 में दुनिया भर में लगभग 3.7 बिलियन टन सीमेंट का उत्पादन या उपयोग किया जाता था। वहीं 2023 में यह मात्रा बढ़कर 6.5 मिलियन टन हो गयी है। लगभग दुगुनी के आसपास। सीमेंट की यह वृद्धि, यह डर पैदा करता है कि शहरीकरण, औद्योगिकरण और सुविधाकरण का यह बहाव दुनिया को कहीं ऐसे मकाम पर ले जा कर ना खड़ा कर दे जहाँ धरती सूरज की तर्ज पर आग से जलकर भुन जाए।

सीमेंट के उत्पादन और उपयोग से मृदा प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। सीमेंट के उत्पादन में चूना, पत्थर और एल्युमिना को ऊँचे तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में धूल और धुएँ का उत्सर्जन होता है। वैज्ञानिक व विद्वान यह खूब जानते हैं की धूल और धुँआ मृदा में और वायुमंडल में प्रवेश करने से प्रदूषण को काफी बढ़े पैमाने पर देखना पड़ता है। जैसा की सीमेंट का अपना स्वभाव है कि वह पानी को अधिक खपत करता है फिर बाद में पानी शिवरेज के रूप में छोड़ा

जाता है। जिससे जल प्रदूषण भी काफी होता है। निर्माण कार्य में भी सीमेंट व कंक्रीट के इस्तेमाल से जल प्रदूषण देखा जाता है। साथ कंक्रीट के एक बड़े अवयव के रूप में जाना जाने वाला सीमेंट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी बड़ा रोल करता है। इसके निर्माण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन होता है जिससे वायुमंडल में गर्मी बढ़ जाती है। साथ ही एक कंक्रीट तमाम रोशनीयों, वायुमंडल की उष्मा व सूरज की किरणों को अवशोषित कर उसे और अधिक ताप बढ़ाकर इसी धरती के वायुमंडल को सौंप देता है जिससे धरती के वायुमंडल में काफी जलन व आग फैल जाती है।

विगत कुछ वर्षों से बहुत बार सुना जाता है कि गर्मी की फसलों जैसे गेहूँ में आग लगने की बात खबरों में आती है। आज से 50 से 100 वर्ष पहले कभी भी फसलों में स्वतः आग लगने की घटना प्रकाश में नहीं आती थी। कंक्रीट के बढ़ते प्रभाव से बढ़े ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब स्वाभाविक रूप से सूखी फसलें अपने आप जल जाती हैं। शहरों की देखा देखी अब गाँव में भी हर आदमी द्वारा कंक्रीट के मकान व छतों का निर्माण काफी तेजी से किया जा रहा है। पहले पत्थरों की सड़क बनती थी अब डामर की सड़कों को भी बनाना छोड़कर आरसीसी सड़कें ही बनाई जा रही हैं। ब्रिज भी आरसीसी ही बनाये जा रहे हैं ऐसे में घर से बाहर तक पसरते कंक्रीट ने विश्व के तापमान को बढ़ा दिया है तथा तापमान बढ़ने के कारण बड़े स्तर पर जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जब बारिश होनी चाहिए तो सूखा पड़ रहा है, जब मौसम खुश होना चाहिए तो बारिश हो रही है। प्रकृति अपने सहज चलन-प्रवाह को बदल रही है। मौसम अब पर्यावरण चक्र के हिसाब से नहीं बल्कि मानव के हस्तक्षेप से प्रभावित तथा परिवर्तित समय पर आ और जा रहे हैं। अपनी जरूरत के दृष्टिगत अपने अनुकूल धरती व संसार को करते-करते आदमी संपूर्ण सृष्टि को अपने अनुसार कर लेने पर आमादा है। कुछ दिनों बाद यह सृष्टि में रहेगा या नहीं इस बात पर भी प्रश्न उठने लगा है। साथ ही प्रश्न यह भी उठ रहा है कि क्या मनुष्य जाति और जातियों के लिए खतरा हो गयई है? कंक्रीट के उपयोग को



वर्ष	सीमेंट का उत्पादन (टन)
2013	3.7 बिलियन
2014	3.9 बिलियन
2015	4.1 बिलियन
2016	4.3 बिलियन
2017	4.5 बिलियन
2018	4.6 बिलियन
2019	4.8 बिलियन
2020	4.9 बिलियन
2021	5.1 बिलियन
2022	5.3 बिलियन
2023	5.5 बिलियन

रोकना तो संभव नहीं है, पर इसके सार्थक उपयोग के लिए सरकारों को सोचना पड़ेगा। समाज को और तमाम स्वयं सेवी संगठनों को भी इस ओर सोचना होगा कि क्या हमें अब ऋषियों की कुटिया की तरफ लौटने की घड़ी आ रही है? व्यापक धरती पर बहुमंजी इमारत की आवश्यकता क्या सही में है? या हम कोरे व्यापार में आकण्ठ डूबे जा रहे हैं। खासकर ऐसा निर्माण किस काम का है जो सौ-पचास साल बाद फिर दिवस टावर की तरह जमींदोज करना पड़े और उसकी धूल से सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का पूरा सामुदायिक जीवन प्रभावित हो। क्या हम हाइ मांस के बने कोमल लोगों को कुत्रिम पत्थर व कंक्रीट की उतनी जगहों पर जरूरत है जितनी हम उसके लिए दीवानी हैं? सवाल अनेक हैं पर उत्तर सिर्फ एक ही है, कि सबको जागना होगा और इसके उपयोग में और सावधानी लानी होगी, जग कल्याण के स्तर पर इसकी वाकई समीक्षा करनी होगी। समाज स्वयं न चेतें तो सरकार किस लिये है? अब यह सपना नहीं है कि पूरी धरती को कंक्रीट की परत ढँक लेगी। और चारों ओर आग बरसेगी। क्या आप आग उगलती पत्थर की दुनिया देखना चाहेंगे? मैं तो नहीं चाहता।

लेखक अनिवार्य प्रश्न अखबार, उद्धार संस्था और स्वाही प्रकाशन के संस्थापक हैं।

अमृत बेला में, अमृतप्राणा प्रकृति की, अमृत वर्षा



डा. डी. आर. विश्व कर्मा
लेखक मुख्य विकास अधिकारी रहे हैं

अमृत बेला को ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, इस समय प्रकृति शांत रहती है। यह समय स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आइए ब्रह्म मुहूर्त को और अच्छे से समझें। ब्रह्म मुहूर्त दो शब्दों के संयोजन से

बना है, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, और मुहूर्त का मतलब समय, हमारे मनीषियों ने एक मुहूर्त के समय को 48 मिनट का बताया है। हम सभी जानते हैं कि भौगोलिक स्थिति और ऋतुओं के अनुसार सूर्योदय का समय बदलता रहता है, इस सूर्योदय से दो मुहूर्त यानि 96 मिनट पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्मबेला कहते हैं। इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर होता है। हमारे ऋषियों, महर्षियों ने कहा है,

“ ब्रह्म मुहूर्तं सुष्येत ” यानि ब्रह्म बेला में जग जाने की हिदायतें दी हैं। इस समय काल में प्रकृति अमृत प्राणा होती है।

भू वैज्ञानिकों का भी कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय बदलता रहता है। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय को 4:24 बजे से 5:12 बजे का मानते हैं, कुछ लोग 4 बजे से 6 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। गर्मी, जाड़े व ऋतुओं में ब्रह्म मुहूर्त का समय भिन्न भिन्न हो जाता है क्योंकि सूर्योदय का समय भी ऋतु अनुसार बदल जाता है।

कहते हैं कि जिस किसी को अच्छी सेहत, ताजगी व ऊर्जा पाने की लालसा हो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास करना

चाहिए। इस समय व्यक्ति का दिमाग स्थिर रहता है, वातावरण स्वच्छ होने के कारण देव उपासना, ध्यान, योग, पूजा का भी यह उपयुक्त समय होता है। तन, मन, बुद्धि को पुष्ट करने का यह अति उत्तम समय माना जाता है।

अष्टांग हृदय में भी वर्णित है कि जो साधक ध्यान में गहरे उतरना चाहते हों उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने का अभ्यास करना अति उत्तम होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं उनको उग्र बढ़ने की क्रिया धीमी होने लगती है।

ब्रह्म मुहूर्त में जागने के वैज्ञानिकों ने भी अनेक फायदे बताए हैं ब्रह्म मुहूर्त में पिट्यूटरी गैलैंड का स्राव ज्यादा होता है, इस समय व्यक्ति को गुस्सा, लालच, ईर्ष्या कम होता है। अचेतन मन ज्यादा कारगर होता है। नकारात्मकता कम होती है। शरीर में स्फूर्ति ज्यादा होती है। इस समय व्यक्ति में सृजनात्मकता की अतिवृद्धि होती है, जो कुछ भी पढ़ा जाता है, उसकी मस्तिष्क में धारणा अच्छी होती है। वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त का समय जादुई समय होता है। निरोगी एवम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वालों को एवम शिखर पर पहुँचने की आकांक्षा रखने वालों

को ब्रह्म मुहूर्त में जागना नितांत आवश्यक है। यह समय बल वर्धक एवम सौंदर्य को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। एक अंग्रेजी कहावत भी कही जाती है,

Early to bed and early to rise, makes a man healthy wealthy and wise पौराणिक आख्यानों व शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के लाभों का भी जिक्र हुआ है, आइए उस पर भी अनुशीलन करें।

ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु की प्राप्ति होती है, ऐसा होने से शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है।

ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति पशु पक्षी जग जाते हैं, कलरव करते हैं, पुष्प खिल जाते हैं, मुर्गें बाग देते हैं, प्रकृति चैतन्य रहती है।

ब्रह्म मुहूर्त व आयुर्वेद, आयुर्वेद में वर्णित है कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति अमृत तुल्य होती है, उस समय में बहने वाली वायु कई रोगों की दवा भी मानी जाती है, जो संजीवनी शक्ति का कार्य करती है। इस



मुहूर्त में टहलने का परिणाम सर्वोत्तम होता है। शरीर, मन, मस्तिष्क में स्फूर्ति, ताजगी आती है। व्यक्ति को सुख, समृद्धि, सफलता की प्राप्ति हेतु ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जग जाना चाहिए। शास्त्रों, वेदों व पौराणिक आख्यानों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तमाम फायदे बताए गए हैं।

ऋग्वेद में कहा गया है कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य सफलता की प्राप्ति हेतु ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जग जाना चाहिए। शास्त्रों, वेदों व पौराणिक आख्यानों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तमाम फायदे बताए गए हैं।

ताकतवर और दीर्घायु होता है।

सामवेद में वर्णित है कि व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले शौच व स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस समय में शुद्ध व निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। अथर्व वेद ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कहता है कि सूरज

उगने के बाद भी जो व्यक्ति नहीं उठता या जागता है, उसका तेज क्लम हो जाता है। उक्त विवेक्षण से हमें ज्ञात होता है कि कितना लाभ प्रद होता है ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना।

भारतीय समाज से क्या कभी खत्म हो पायेगी दहेज प्रथा



रविन्द्र प्रजापति

दहेज प्रथा भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो समाज में सामाजिक, आर्थिक, और मानसिक स्तर पर गहरा प्रभाव डालता है। यह एक प्राचीन प्रथा है जिसमें विवाह के समय दुल्हन के परिवार द्वारा धन, संपत्ति, और अन्य वस्तुओं की मांग की जाती है। यह प्रथा विवाह के परिवार द्वारा न्यूनतम या अनिवार्य धनराशि के प्रदान को बढ़ा देती है, जिससे समाज में आर्थिक दबाव बढ़ता है।

दहेज प्रथा एक समस्या है जो भारतीय समाज में गहरे रूप से जड़ जमा चुकी है।

इसे समाप्त करने के लिए समाज, सरकार और संगठनों को संगठित तरीके से कदम उठाने चाहिए। दहेज प्रथा का नाश समाज में समानता, जागरूकता और समझदारी के माध्यम से संभव है। इसे खत्म करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी परिवर्तन आवश्यक हैं।

दहेज प्रथा भारतीय समाज की भूमि में गहरी जड़ें डाल चुकी है, जिसका परिणाम यह होता है कि बड़े भाग में लोगों के मानसिकता में इसको स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। इसे एक अनिवार्य और मानवता विरोधी प्रथा के रूप में देखा जाता है। यह महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करती है और उन्हें समाज में असमानता का सामना करना पड़ता है।

दहेज प्रथा का मुख्य कारण है लोगों की सोच में बदलाव नहीं आना। समाज में इसे मान्यता दी जाती है और इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है। महिलाओं की निगरानी और उनके साथ समानता की मांग करने की जरूरत है।

दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए उपायों की जरूरत है। सरकारी नीतियों को मजबूत करने के साथ-साथ समाज में जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। बच्चों को शिक्षा में समानता और सही जागरूकता देना चाहिए।

इस समस्या को हल करने के लिए

आपको समाज में जागरूकता फैलानी होगी। समाज में समानता की भावना और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करने की आदत डालनी चाहिए।

इस समस्या का समाधान समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए सामाजिक संगठनों, सरकारी अधिकारियों और समाज के नेताओं को साथ मिलकर काम करना होगा। कई लोग इसे लेकर अब निराश हो चुके हैं लेकिन विद्वानों का मानना है कि इसे समाप्त करना आज भी संभव है। इस समस्या को हल करने के लिए हमें समाज के हर स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है।

पहला कदम है जागरूकता। लोगों को दहेज प्रथा के खतरों और उसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए। समाज में इस प्रथा को नकारने और महिलाओं को समानता और सम्मान की दिशा में बदलाव लाने की जरूरत है। सामाजिक मीडिया, शिक्षा, अभियान और सामाजिक संगठनों के माध्यम से जागरूकता फैलानी चाहिए।

दूसरा कदम है समानता की भावना को प्रोत्साहित करना। समाज में महिलाओं को समान अधिकार और स्थान देना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, और स्वतंत्रता का पूरा हक देना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

तीसरा कदम है कानूनी प्रणाली को

मजबूत करना। सरकार को दहेज प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए। वहाँ पर कठोर कानून होने चाहिए जो इस प्रथा को बंद करें और उसका पालन-पोषण करें।

चौथा कदम है समाज में सहयोग और सहभागिता को बढ़ाना। समाज के हर व्यक्ति को इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। साथ मिलकर महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान

की दिशा में काम करना चाहिए। पाँचवा कदम है विकल्पों का प्रदान करना। समाज में विभिन्न तरीकों से इस प्रथा को समाप्त करने के लिए समाधान ढूँढने की जरूरत है। जैसे कि, शैक्षिक कार्यक्रम, बचत योजनाएँ, समाज सेवा योजनाएँ, और समाज में दहेज के खिलाफ जागरूकता अभियान।

दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए हमें



दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। यह समाज की सोच को बदलकर समाज में समानता और समझदारी लाने में मदद करेगा। असम्भव तो लगता है पर इसे दूर किया जा सकता है। समाज इससे मुक्ति पा सकता है।

अंततः कहा जाये तो दहेज प्रथा एक ऐसी सोच है जो समाज की

समाज में जागरूकता, समर्थन, और संघर्ष की जरूरत है। यह समस्या एकमात्र सरकार या संगठनों के समाधान से ही नहीं, समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी से हल हो सकती है।

